वर्ष 01 | अंक 02 | मार्च 2024 | मूल्य 100/-

प्रयास करेंट अफेयर्स

UPSC | BPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मासिक पत्रिका

मुख्य आकर्षण

बिहार बजट 2024-25 | सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द किया | भारत में किसान आंदोलन और MSP का मुद्दा
रायसीना डायलॉग 2024 | INSAT-3DS मिशन | CMS पक्षकारों का COP14 सम्मेलन | श्री कल्कि धाम मंदिर
पाँच व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित | 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
भारत टेक्स 2024 | बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स

दैनिक अपडेट्स के लिए जुड़ें : Prayas IAS Academy

प्रयास
IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC

ADMISSION OPEN
upto 50% OFF*

ATTENTION
UPSC / BPSC Aspirants
Boost your AIR with

GS TARGET COURSE
FOR BPSC & UPSC

हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM
MODE: Offline & Online

JOIN THE TEAM OF "Experienced & Renowned Faculties at PRAYAS IAS ACADEMY"

Mr. M K Sahay
Academic Director, PRAYAS IAS
Ex. Sr. Faculty (History) RAU'S IAS, Delhi
27 years & above Experience

Mr. Neeraj Nachiketa
Ex. Sr. Faculty (Sc. Tech)Vajiram & Ravi, Delhi
25 years & above Experience

Mr. DK Upadhyay
GEOGRAPHY

Mr. Satyam Kumar
CSAT & DI

Mr. Prabhat Kumar
ESSAY

Mr. Kiran Anishetti
POLITY, IR & GOVERNANCE

Mr. Nitin Kumar
POLITY, IR & GOVERNANCE

Md. Parvej
POLITY, IR & GOVERNANCE

Mr Amit Mathur
ECONOMY

Md. Rizwan Alam
ETHICS

Mr. Abhishek Tiwari
CURRENT AFFAIR

प्रयास करेंट अफेयर्स

वर्ष 01 | अंक 02 | मार्च 2024 | मूल्य - 100/-

प्रधान संपादक	:	राहुल राज
संपादकीय सलाहकार	:	एस. के. सिंह, एम. के सहाय, डी.के. उपाध्याय, सत्यम कुमार, प्रभात कुमार सेतु
कार्यकारी संपादक	:	राजेश प्रियदर्शी
संपादन सहयोग	:	टीम प्रयास IAS
लेआउट एवं डिजाइन	:	निशांत कुमार झा

प्रयास IAS ACADEMY

कार्यालय

Pushpanjali Palace,
Boring Road Chauraha,
Patna-800001

8818810183 | 8818810184

www.prayasiasacademy.com

prayasiasacademy101@gmail.com

prayasiasacademy

© कॉपीराइट : PRAYAS IAS ACADEMY

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व सम्पादक ने हर प्रकार की सावधानी बरती है। फिर भी किसी प्रविष्टि/तथ्य सम्बंधित किसी प्रकार के वाद पर सम्पादक मंडल जिम्मेदार नहीं होगा। सभी विवादों का निपटारा पटना (बिहार) न्यायिक क्षेत्र में होगा।

Editor's Desk

प्रिय पाठकों,

"आत्म अनुशासन के बिना आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे"

उपर्युक्त कथन से तात्पर्य है कि आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। अनुशासन हमसे वह करवाता है, जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता। आत्म अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, न लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, और ना ही मुसीबत के पलों का सामना कर पाएंगे।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है, बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन सफल नहीं हो सकता है। विद्यार्थी जीवन में मनमाना काम करने की इच्छा सफलता प्राप्ति में रुकावट होती है। यदि अनुशासित होकर सही दिशा में लगातार मेहनत की जाय तो सफलता अवश्य ही मिलती है ।

इसके मद्देनजर विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने की दिशा में देश के अनुभवी मेंटर्स की एक नई दस्तक है - PRAYAS IAS ACADEMY. जहाँ देश के अनुभवी शिक्षकों, विषय-विशेषज्ञों एवं मेंटर्स द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करायी जाती है। यहाँ करेंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, न्यूज पेपर रिडिंग, राइटिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डवलपमेंट एवं टेस्ट सीरीज से संबंधित कक्षा का संचालन किया जाता है।

साथ ही सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिये इस संस्थान द्वारा "प्रयास करेंट अफेयर्स" मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है। पहले अंक की अपार सफलता के पश्चात् इस पत्रिका का दूसरे अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। आपको बता दें कि इस पत्रिका में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का संकलन किया गया है, जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न के अनुरूप है ।

प्रयास करेंट अफेयर्स पत्रिका आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन और पाठ्य-सामग्री प्रदान करता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिये इसका सर्वोत्तम उपयोग करना आप पर निर्भर है। हम आशा करते हैं कि यह पत्रिका आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

आपकी शानदार सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं सहित !

राहुल राज
(प्रबंध निदेशक)

इस अंक में .....

बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स 03-05

- बिहार बजट 2024 25
- बिहार फ्लोर टेस्ट
- नागी पक्षी महोत्सव-2024
- राष्ट्रीय आयुष मिशन की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक
- स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना

राष्ट्रीय परिदृश्य 06-10

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024
- आयुष समग्र कल्याण केंद्र
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द किया
- जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC)
- जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल
- राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन -2024

आर्थिक परिदृश्य 11-14

- भारत में किसान आंदोलन और MSP का मुद्दा
- श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाओं की शुरुआत
- जूट उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन
- समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग
- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी
- विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम में संशोधन

वैश्विक परिदृश्य 15-17

- भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय बैठक
- आसियान-भारत माल व्यापार समझौता
- INDUS-X शिखर सम्मेलन
- रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 18-19

- डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन-2023
- 'वायु शक्ति-24' अभ्यास
- GSLV-F14/INSAT-3DS मिशन
- i-ऑन्कोलॉजी AI प्रोजेक्ट

भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 20-23

- विश्व आर्द्रभूमि दिवस
- समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- नोखरा सौर परियोजना का उद्घाटन
- जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन
- CMS के पक्षकारों का 14वाँ सम्मेलन (COP-14)
- बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

इतिहास, कला एवं संस्कृति 24-26

- महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती
- आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी का निधन
- श्री कल्कि धाम मंदिर
- छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती
- सम्मक्का-सरक्का मेदारम जथारा त्योहार
- संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती

अन्य सुर्खियाँ 27-29

- पांच व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित
- SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024
- अभ्यास मिलन 2024
- 58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार
- भारत टेक्स 2024

महत्वपूर्ण तथ्य : एक नजर में 30-31

करेंट अफेयर्स आधारित प्रश्न 32

बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स

बिहार बजट 2024 25

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,725.72 (2.78 लाख) करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य रहे, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आकार 2 लाख 61 हजार करोड़ रुपये से 2024-25 के बजट आकार में 16,540 करोड़ की बढ़ोतरी की गयी है ।
- वित्त मंत्री के अनुसार राज्य ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वहीं चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।
- इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया है।
- सरकार ने सभी तबके खासकर गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए कुल बजट आकार का 38% यानी 1,08,384 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।
- प्रस्तुत किये गए बजट में शिक्षा विभाग को 22,200.35 करोड़ रुपए (22.20%) धनराशि आवंटित करके सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
- वहीं ग्रामीण विकास विभाग को 13,840.56 करोड़ रुपए (13.84%), समाज कल्याण विभाग को 8,191.79 करोड़ रुपए (8.19%), ग्रामीण कार्य के लिए 7,409.13 करोड़ रुपए (7.41%), स्वास्थ्य विभाग को 7,117.56 करोड़ रुपए (7.12%), कृषि के लिए 2782 करोड़ रुपए (2.78%) आवंटित किये गए।

- सरकार ने 7 निश्चय योजना-2 कार्यक्रम के तहत सुशासन योजनाओं पर 5,040 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है। साथ ही सरकार अकेले कई छात्रवृत्ति योजनाओं पर 3,073.26 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- बजट में 1,121.41 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है और 2.98% का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। इसमें 3.48 लाख करोड़ रुपए का बकाया ऋण भी दिखाया गया है।
- 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 225676.99 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह बजट आकार 2,78,725.72 करोड़ रुपये का 80.97 प्रतिशत है ।
- 2024-25 में केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में 52160.62 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह 2023-24 के बजट अनुमान 53,377.92 करोड़ की तुलना में 1217.30 करोड़ रुपये अधिक है।

कहां-कितना खर्च होगा

- वेतन पर 71816.82 करोड़
- पेंशन पर 31796.13 करोड़
- सूद अदायगी पर 20526.19 करोड़
- कर्ज अदायगी में 22,392.72 करोड़

किस कर से कितना राजस्व

- वाणिज्य कर से 42,500 करोड़
- स्टांप एवं निबंधन कर से 7,500 करोड़
- परिवहन कर से 3700 करोड़
- भू राजस्व से 600 करोड़
- सरकार को अपने कर राजस्व के रूप में मिलेंगे 54,300 करोड़

बिहार फ्लोर टेस्ट

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) गठबंधन सरकार ने 129 मतों से विश्वास प्रस्ताव जीत लिया।
- साथ ही बिहार विधानसभा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव 125 सदस्यों के समर्थन से पारित भी हो गया।

- इस दौरान राजद नेता ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले पार्टी विधायकों के सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच बैठने पर आपत्ति जताते हुए व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तीन विधान सभा सदस्य (विधायक) सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे देखे गए।

फ्लोर टेस्ट क्या होता है?

- फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है।
- विदित हो कि गठबंधन सरकार के मामले में, मुख्यमंत्री को विश्वास मत लाने और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है।
- स्पष्ट बहुमत के अभाव में, जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं, तो राज्यपाल यह देखने के लिये विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने हेतु किसके पास बहुमत है।
- इस स्थिति में कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या वोट न देने का विकल्प चुन सकते हैं। फिर संख्या केवल उन विधायकों के आधार पर मानी जाती है जो वोट देने के लिये मौजूद थे।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

- इसे No Confidence Motion भी कहते हैं। यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये लोकसभा या विधान सभा में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती हैं जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।

नागी पक्षी महोत्सव-2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जमुई में तीन दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार ने किया।
- महोत्सव का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। इस महोत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को इन प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस महोत्सव का आयोजन जमुई के नागी-नकटी झील के आस-पास किया गया है । यह जलाशय करीब 521 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस जलाशय का शिलान्यास 1955-56 में किया गया था लेकिन वर्ष 1984 में सरकार ने इसे पक्षी अभ्यारण के रूप में स्वीकृति दी थी।
- यहां साइबेरियन सहित अन्य प्रवासी और देशी पक्षियों के लगभग 150 प्रजातियां जाड़े के मौसम में डेरा डालते हैं। यहां नवंबर माह से मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और यह सिलसिला अप्रैल माह तक जारी रहता है।
- इसमें लिटल ग्रेबे, लिटल कार्मोरेंट, ग्रेहेरॉन, पर्पल हेरॉन, इंडियन पाण्ड्स हेरॉन, केटल एग्रेट, लिटल एग्रेट, सर्बियन क्रेन, डामी डेथ, पोचार्ड, लालसर, ओपन बिल स्टाप, काली गर्दन वाली पनडुब्बी, छोटी पनडुब्बी, वन कौआ आदि प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशन की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक

सुर्खियों में क्यों?

- 15 फरवरी 2024 को केन्द्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित छह राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग लिया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अपने संबंधित राज्य वार्षिक कार्य

योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023-24 तक एनएएम के एक घटक के रूप में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष मंत्रालय द्वारा 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को मंजूरी दी गई है।
- हाल ही में एनएएम योजना के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ध्यान रहे, आयुष मंत्रालय ने 2014-15 से अब तक एनएएम के तहत 07 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को 1712.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- एनएएम के तहत, मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान अयोध्या में एक नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वाराणसी में नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए भी सहयोग दिया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में

- इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
- NAM का उद्देश्य उन राज्यों में मौजूदा आयुष शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन और नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये आयुष क्षेत्र का विस्तार शामिल है। यह मिशन देश में विशेष रूप से कमज़ोर और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ/शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को संबोधित करता है।
- ध्यान रहे, सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगुसराय ज़िले के पपरौर ग्राम

पंचायत में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' परियोजना का उद्घाटन किया।

स्मार्ट ग्राम पंचायत के बारे में

- यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी में परिवर्तन के साथ बेगुसराय की सभी ग्राम पंचायतों तक P M - वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा पहुँचाना है।
- ध्यान रहे, बेगूसराय अब PM-वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला ज़िला बन गया है।
- इस परियोजना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वित्त पोषित किया गया है। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बेगुसराय और रोहतास में ग्राम पंचायतों तक पीएम-वाणी सेवाओं का विस्तार करना है। ध्यान रहे, RGSA पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इसका कार्यान्वन बीएसएनएल के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- यह छात्रों, किसानों, कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर केंद्रित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना तथा डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया है।
- इसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी आदि जैसी भर्ती परीक्षाओं और एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में लीक, कदाचार के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है।

विधेयक का प्रमुख प्रावधान:

- विधेयक का उद्देश्य संगठित गिरोहों और संस्थानों को रोकना है जो मौद्रिक लाभ के लिए अनुचित तरीकों में शामिल हैं, लेकिन यह उम्मीदवारों को इसके प्रावधानों से बचाता है। विधेयक संगठित अपराधों के लिए उच्च सज़ा निर्दिष्ट करता है।
- इस विधेयक में लोक परीक्षा को परिभाषित किया गया है। धारा 2(k) के तहत, लोक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध "लोक परीक्षा प्राधिकरण" या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
- यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सज़ा दी जाएगी।
- विधेयक की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और गैर-शमनयोग्य होंगे।
- इन नामित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के अलावा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग और कर्मचारियों की भर्ती के लिये उनसे जुड़े तथा अधीनस्थ कार्यालय भी नए कानून के दायरे में आएँगे।
- परीक्षाओं के संचालन के लिये सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है और यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।
- यह विधेयक राज्यों द्वारा अपने विवेकाधिकार से इसके अंगीकरण हेतु एक मॉडल मसौदे के रूप में भी कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य आपराधिक तत्त्वों को उनकी राज्य-स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं को बाधित करने से रोकने में राज्यों की सहायता करना है।
- सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, IT तथा भौतिक बुनियादी ढाँचे दोनों के संबंध में राष्ट्रीय सेवा एवं मानक स्तर तैयार करेगी तथा दक्षता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये परीक्षाओं के संचालन हेतु इन मानकों का कार्यान्वन किया जाएगा।

आयुष समग्र कल्याण केंद्र

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में 'आयुष समग्र कल्याण केंद्र' का उद्घाटन किया।
- आयुष समग्र कल्याण केंद्र, आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के सहयोग से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक पहल है।
- आयुष समग्र कल्याण केंद्र एक अत्याधुनिक सुविधा है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए समग्र देखभाल उपलब्ध कराती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।

आयुष मंत्रालय के बारे में

- आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हमारी चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था।
- इससे पहले, 1995 में गठित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (आईएसएम एंड एच) इन प्रणालियों के विकास के लिए जिम्मेदार था।
- इसके बाद नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के रूप में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ध्यातव्य है कि सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इस मिशन का उद्देश्य उन राज्यों में मौजूदा आयुष शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन और नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द किया
(The Supreme Court Strike Down The Electoral Bonds Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme- EBS), जो राजनीतिक दलों को अनाम तरीके से दान प्राप्त की अनुमति देती थी, को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चुनावी बॉण्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर ज़ोर दिया कि सूचित चुनावी निर्णयों के लिये राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग के संबंध में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है।
- SC ने भारतीय स्टेट बैंक को किसी भी अन्य चुनावी बॉण्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और 12 अप्रैल, 2019 से अब तक राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे बॉण्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के विवरण में प्रत्येक बॉण्ड की खरीद की तिथि, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य शामिल होना चाहिये। बाद में ECI 13 मार्च, 2024 तक SBI द्वारा साझा की गई ऐसी सभी जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- गौरतलब है कि SBI चुनावी बॉण्ड जारी करने और भुनाने के लिये अधिकृत एकमात्र बैंक है। इस योजना के तहत किये गए दान पर 100% कर छूट का लाभ मिलता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने EBS और वित्त अधिनियम, 2017; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (RPA) 1951; आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 में किये गए संशोधनों को असंवैधानिक घोषित किया।
  - ❖ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिये महत्त्वपूर्ण कई कानूनों में वित्त अधिनियम, 2017 से पहले के विधिक ढाँचे को बहाल कर दिया।
  - ❖ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C में राजनीतिक दलों को दानकर्त्ता की गोपनीयता के साथ सूचना के अधिकार को संतुलित करते हुए 20,000 रुपए से अधिक के दान का खुलासा करना अनिवार्य है। SC ने पारदर्शिता और गोपनीयता संतुलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए संशोधन को खारिज कर दिया गया।
  - ❖ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 ने कॉर्पोरेट दान को प्रतिबंधित कर दिया और एक सीमा निर्धारित (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 7.5%) की तथा प्रकटीकरण/खुलासे की आवश्यकताओं को लागू किया। SC ने चुनावों पर अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए संशोधन को रद्द कर दिया गया।

चुनावी बॉण्ड क्या हैं?

चुनावी बॉण्ड योजना (EBS) वर्ष 2018 में शुरू की गई जो राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है। ये बॉण्ड वित्तीय साधनों के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें वचन-पत्र या वाहक बॉण्ड के समान, विशेष रूप से राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

❖ EBS की घोषणा पहली बार वर्ष 2017 के बजट सत्र में की गई थी। बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉण्ड को सक्षम करने के लिये वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था।

❖ चुनावी बॉण्ड SBI इसे नामित शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। ये 1000 रुपये, 10000 रुपये, 1 लाख रुपये तथा 1 करोड़ रुपये के कई मूल्यवर्ग में बेचे जाते हैं।

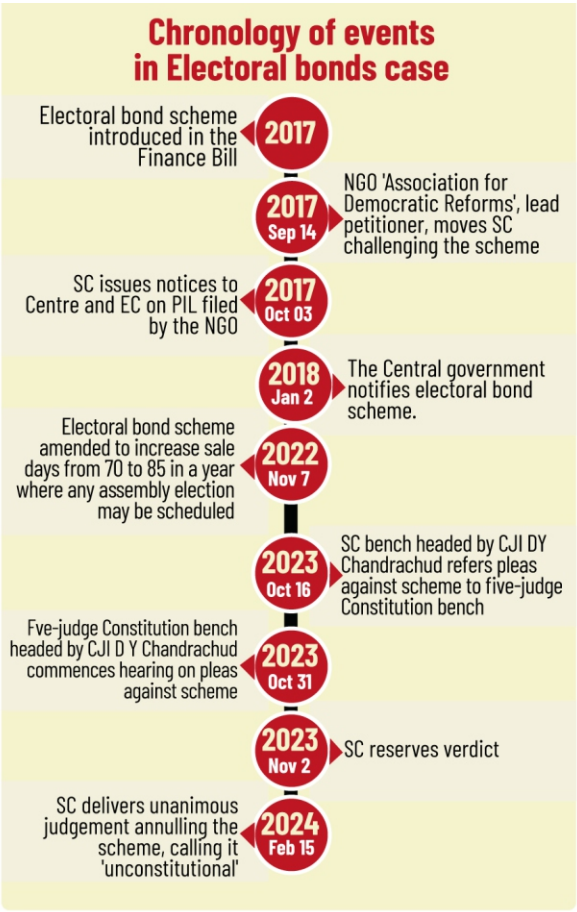

- ❖ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A(b) के तहत 20,000 रुपए से अधिक के दान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। SC ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार को बरकरार रखते हुए संशोधन को रद्द कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का पता लगाने के लिये आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) लागू किया कि इस योजना ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लंघन किया है अथवा नहीं।
  - ❖ गौरतलब है कि आनुपातिकता परीक्षण राज्य की कार्रवाई और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का मूल्यांकन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मानक के रूप में कार्य करता है।
  - ❖ ध्यान रहे, आनुपातिकता परीक्षण को के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 के निर्णय में प्रमुखता दी गई, जिसमें गोपनीयता की पुष्टि मौलिक अधिकार के रूप में की गई।
  - ❖ इस सन्दर्भ में सरकार ने तर्क दिया कि काले धन पर अंकुश लगाना और दानकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करना राज्य के वैध हित हैं। दाताओं की गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने के लिये दाता अनामिकता (दाता से संबंधी जानकारी को उजागर न करना) को अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक वैध राज्य उद्देश्य के रूप में दानकर्त्ता की अनामिकता को खारिज कर दिया और अनामिकता के बजाय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी। न्यायालय ने "दोहरी आनुपातिकता" परीक्षण की अवधारणा को लागू किया जिसके तहत प्रतिस्पर्द्धी मौलिक अधिकारों, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करना शामिल है।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी 2024 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- 'ग्रामीण वॉश क्षेत्र में सतत समाधानों की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण' सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन नेविचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के गतिशील आदान-प्रदान के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विविध हितधारकों को एकजुट किया है।
- यह सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया जहाँ प्रतिभागियों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया, सहयोगात्मक योजना की रणनीति बनाई और ग्रामीण स्वच्छता के लिए नवीन दृष्टिकोणों पर चर्चा की।
- इस सम्मलेन में उत्तर प्रदेश की स्वच्छता क्रांति, बिहार का शौचालय क्लिनिक, मध्य प्रदेश का स्थायी व्यवसाय मॉडल, मेन्स्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में झारखंड का अग्रणी प्रयास, आंध्र प्रदेश की संसाधन प्रबंधन पायलट पर प्रस्तुति, हरियाणा के सामुदायिक सोख्ता गड्ढे और तेलंगाना के बार्थन बैंक को नवीन प्रौद्योगिकियों के तहत प्रस्तुत किया गया।

जल जीवन मिशन क्या है?

- वर्ष 2024 तक हर घर में 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (Functional Household Tap Connection FHTC) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।
- इस मिशन के तहत सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा, सभी मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और नल कनेक्शनों की कार्यक्षमता भी सुनिश्चित की जानी है।
- जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है- "कोई भी पीछे न छूटे"।
- इस मिशन को बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, 'ग्राम जल और स्वच्छता समितियों' (VWSC) या पानी समितियों (Pani Samitis) के माध्यम से एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम सीधे तौर पर 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करता है तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।

देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य इस केंद्र के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है। इसके माध्यम से नौकरी की भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करके, अमृत पीढी के कौशल-समूह को मांग-संचालित उद्योगों में उन्नत किया जाएगा ।
- यह पहल मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य, और आईटी-आईटीईएस जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में युवा शक्ति की क्षमताओं और ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- यह एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो कक्षा और कार्य-आधारित शिक्षा के एक अद्वितीय संयोजन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल के साथ सशक्त बनाता है।
- यह केंद्र सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो औपचारिक कौशल की मांग की पूर्ति करेगा और युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।
- कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) उद्योग विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो उद्योग की बदलती अवश्यकताओं के अनुरूप होगा, मानकीकरण को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जो उद्योगों में कुशल प्रतिभा की मांग को पूरा करेगा।

- यह युवाओं के लिए एक उल्लेखनीय अवसर है जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने के अनुभव प्राप्त करना और प्रसिद्ध संगठनों के साथ संभावित कैरियर के रास्ते तलाशना है।
- इस कार्यक्रम के बाद, ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है।
- ध्यान रहे, वर्ष की शुरुआत में कौशल रथ पहल शुरू की गई थी, जो ओडिशा के संबलपुर, अंगुल और देवगढ़ जिलों में इच्छुक उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई बसें हैं। इसने पहले ही 4000 उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रम मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे डिजिटल साक्षरता, खुदरा और उद्यमशीलता कौशल और क्षेत्र के समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिला है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बारे में

- एनएसडीसी की स्थापना वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देने और लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था।
- यह नेशनल स्किलिंग मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाना था।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) देश में कौशल इकोसिस्टम का प्रमुख वास्तुकार है। यह भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत काम करने वाला एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) उद्यम है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कौशल इकोसिस्टम को तैयार करने और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल बनाने के लिए कौशल भारत मिशन के रणनीतिक कार्यान्वयन और ज्ञान भागीदार बनने के लिए की गई थी।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) उन उद्यमों, स्टार्ट-अप, कंपनियों और संगठनों को सहायता प्रदान करता है जो संभावित कार्यबल को भविष्य के कौशल में अवसरों की दुनिया की पेशकश करके प्रभाव पैदा कर रहे हैं।
- संगठन पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता, उम्मीदवारों को रियायती ऋण के साथ-साथ अन्य नवीन वित्तीय उत्पादों और रणनीतिक साझेदारी के निर्माण की पेशकश करके कौशल में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाने, समर्थन और समन्वय करने के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करता है।

जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को रोग मुक्त बनाना है। इससे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे बीमारियों की रोकथाम पर जोर देने के साथ उनके स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार और सुरक्षा की जा सके।
- आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर की संयुक्त पहल से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए यह स्वास्थ्य पहल शुरू की है।
- इसकी घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए संयुक्त पहल के रूप में की गई है। इस परियोजना से 20,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ होगा।
- इस परियोजना का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में छठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10-18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कवर करना है।
- यह पहल जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अध्ययन करने तथा आयुर्वेद के माध्यम से कुपोषण, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और सिकल सेल रोगों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पूरा करने में सहयोग करेंगे।
- ध्यान रहे, जनजातीय विकास के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2022 में आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के अनुसार सीसीआरएएस ने 20 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 72 पोषण वाटिकाएं विकसित कीं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में

- `एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत 1997-98 में की गई थी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- एकलव्य विद्यालय न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि अच्छे स्वास्थ्य सहित छात्रों के समग्र विकास पर फोकस करते हैं। इन स्कूलों का फोकस खेल और कौशल विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं पर है।
- वर्तमान में देश भर में 401 कार्यात्मक स्कूल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2024 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन -2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन -2024 का उद्घाटन किया।
- यह तीन दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 फरवरी 2024 तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर की एक पहल है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक सहयोगी शिक्षण मंच बनाना है।
- सम्मेलन स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के विचारों पर केंद्रित है, जो प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन में योगदान देता है।
- यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), तपेदिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करने में नवीन दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जिसमें जूनोटिक रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के पहलुओं सहित एक स्वास्थ्य के लिए सहयोग पर जोर दिया गया है।
- यह आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के बारे में भी पता लगाएगा।

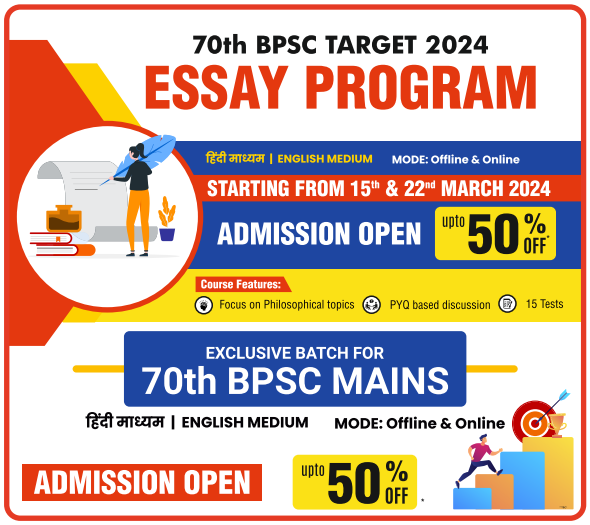

भारत में किसान आंदोलन और MSP का मुद्दा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।
- इससे पहले वर्ष 2020 में किसानों ने, दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों (कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020,मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020) का विरोध किया गया था, जिसके कारण वर्ष 2021 में इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया।

किसान आंदोलन के कारण

- सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिये एक कानून और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिये पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया (जिसे 'सी2' कहा जाता है) शामिल है।
- किसानों और मज़दूरों की पूर्ण क़र्ज़ माफी हो।
- साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन हो, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और संग्राहक दर (collector rate) से चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है।
- वर्ष 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिये मुआवज़ा और अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए।
- भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर हो जाना चाहिये और सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर रोक लगा देनी चाहिये।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या होता है?

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Prices), किसी भी फसल का वह 'न्यूनतम मूल्य' होता है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।
- MSP का निर्धारण 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (Commission for Agricultural Costs and Prices–CACP) की संस्तुति पर, एक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसकी गणना, किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना कीमत के आधार पर की जाती है।
- वर्तमान में, CACP, 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित तथा लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश किया है। अधिदिष्ट फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) में 7 अनाज (धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी), 5 दालें (चना, अरहर/तूर, मूंग, उरद और मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और रामतिल) के अलावा कच्चा कपास, कच्चा जूट और नारियल (कोपरा) को शामिल किया गया है।

MSP से संबंधित चुनौतियाँ

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत नियमित रूप से की जाती है।

- चूंकि राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है और जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाती हैं, वहां के किसानो को अधिक लाभ होता है। जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं।
- MSP आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर भी निर्भर होती है, और छोटे किसानों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
- MSP योजना के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ मौजूद हैं। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त होता है अर्थात देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित हैं।
- सरकार को MSP पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या हो सकती है। साथ ही यह फसल पैटर्न को भी विकृत (distort) कर सकता है क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में MSP वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- इसके व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, जैवविविधता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
- MSP किसानों के बीच आपसी भेदभाव का कारण बन सकती है | ऐसा कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है।
- सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाओं की शुरुआत

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका तथा मॉरीशस में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) सेवाओं एवं रुपे कार्ड (RuPay card) सेवाओं के शुभारंभ का मॉरीशस में उद्घाटन किया।

- इस परियोजना को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत मॉरीशस तथा श्रीलंका के साझेदार बैंकों/गैर-बैंकों के साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड(NPCL) द्वारा विकसित तथा निष्पादित किया गया है।

रुपे कार्ड (RuPay card) एवं UPI क्या होता है?

- रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है जिसका उपयोग पूरे भारत में ATMs, पॉइंट ऑफ सेल(PoS) उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर किया जा सकता है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) वर्ष 2016 में NPCI द्वारा विकसित एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। यह प्रणाली IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) बुनियादी अवसंरचना पर बनाया गया है और उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
- UPI कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक मोबाइल एप्लिकेशन में विलय करने की अनुमति देता है।
- UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल हैं। जबकि रुपे कार्ड स्वीकार करने वाले देश में मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है।

जूट उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने 'जूट उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन' पर 53वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। लगभग 73% जूट उद्योग का केंद्र (कुल 108 जूट मिलों में से 79) पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
- यह एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद होने के कारण 'सुरक्षित' पैकेजिंग के सभी मानकों को पूरा करता है।
- भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन में 70% का योगदान देता है। जूट उद्योग प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 3.7 लाख श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करता है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में कुल 1,246,500 मीट्रिक टन (MT) के साथ महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- जूट से निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 177,270 मीट्रिक टन हो गया, जो कुल उत्पादन का लगभग 14% है। यह वर्ष 2019-20 के निर्यात के आँकड़ों की तुलना में 56% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

- इसी अवधि में भारत ने 121.26 हज़ार मीट्रिक टन कच्चे जूट का आयात किया। उच्च गुणवत्ता वाले जूट की मांग के कारण बांग्लादेश से जूट का आयात किया गया है।

जूट के बारे में

- जूट एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल कृषि उत्पाद है ।
- जूट की कृषि के लिये तापमान: 25-35°C के बीच, वर्षा लगभग 150-250 सेमी. एवं जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है ।
- भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। लेकिन जूट मीलों की सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश में स्थित है|
- जूट की कृषि तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में केंद्रित है, जो उत्पादन का 99% हिस्सा है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी पर केंद्रित है।
- बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णियाँ जिला में होता है ।
- जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग जूट की थैली, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है।

समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने भारत के जैविक निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग बनाया है। यह प्रभाग अब देश की जैविक निर्यात क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों में समन्वय के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है।
- इसके अलावा अपेडा ने उत्तराखंड और सिक्किम से जैविक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप भी तैयार किया है ।
- इस योजना का फोकस कृषि प्रथाओं को बढ़ाने, प्रमाणन प्रक्रियाओं को अधिकतम करने तथा प्रमुख निर्यात उत्पादों की पहचान करने पर है। साथ ही योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रमुखता में वृद्धि करना है।
- इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) में सुधार किया जा रहा है। एनपीओपी दिशानिर्देशों में होने वाले संशोधनों का उद्देश्य यूरोपीय संघ विनियमन सहित प्रमुख वैश्विक नियमों और मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।

जैविक कृषि का महत्व

- जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है, जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक उर्वरक और खाद जैसे- कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है ।
- इस प्रकार की कृषि से भूमि की उपजाऊ क्षमता एवं जल स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है। यह पर्यावरण संबंधी लाभ के साथ-साथ स्वच्छ, स्वस्थ, गैर-रासायनिक उपज किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये लाभदायक है।
- ध्यान रहे, सिक्किम वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने रणनीतिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे उपग्रह निर्माण, लॉन्च वाहन निर्माण और जमीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण में अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की अनुमति मिल गई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीति उपग्रहों, जमीनी खंडों और उपयोगकर्ता खंडों के लिए घटकों और प्रणालियों या उप-प्रणालियों के निर्माण में 100% FDI सुनिश्चित करती है।
- सैटेलाइट विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए 74 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है। 74 प्रतिशत से अधिक ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।

- लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों के विकास और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण के लिए, स्वचालित मार्ग के तहत FDI 49 प्रतिशत तय किया गया है।
- इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत में अत्याधुनिक तकनीकों को पेश करना, घरेलू अंतरिक्ष खिलाड़ियों को वैश्विक बड़ी कंपनियों के साथ मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना और अंतरिक्ष संपत्ति निर्माण क्षमताओं में तेजी से वृद्धि के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन, टेलीमेडिसिन, इंटरनेट कनेक्टिविटी में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या होता है?

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
- यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है। FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है।

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम में संशोधन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ताओं के परिसर में रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने में आसानी बढ़ाने और तेजी से स्थापना की सुविधा के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। 10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता से छूट दी गई है। 10 किलोवाट से अधिक क्षमता की प्रणालियों के लिए, व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने की समयसीमा को बीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, वितरण लाइसेंस धारकों के लिए रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम चालू करने की समय-सीमा तीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन कर दी गई है।
- संशोधन बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन का प्रकार चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं और आवासीय सोसायटियों में कॉमन एरिया और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- संशोधनों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत को जांचने के लिए वितरण कंपनी द्वारा चेक मीटर लगाए जाने का भी प्रावधान है।
- गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2020 को बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किया गया। इसके तहत पूरे भारत में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मानक निर्धारित किए गए। इन नियमों में बिलिंग, शिकायतें, मुआवजा और नए कनेक्शन की समयसीमा जैसे पहलू शामिल हैं। ये नियम प्रोज्यूमर (ऐसे व्यक्ति जो उपभोग और उत्पादन दोनों करते हैं) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं।

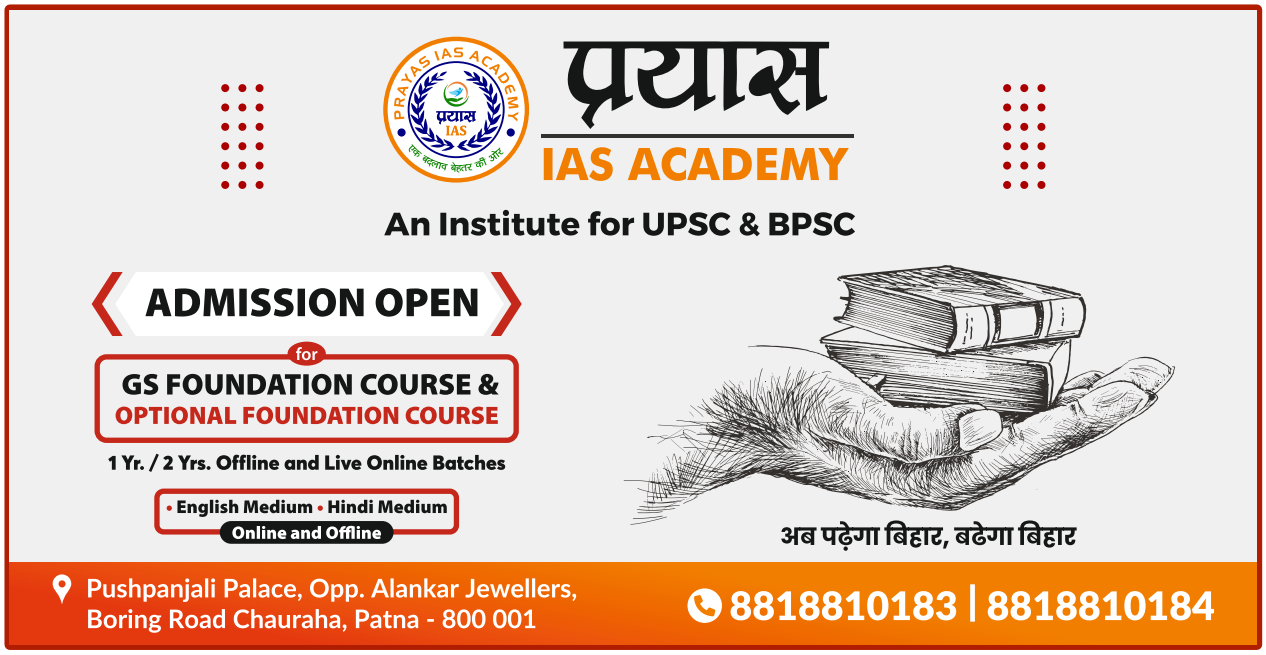

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय बैठक

सुर्खियों में क्यों?

- 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की यह कतर की दूसरी यात्रा है। इसके पहले वो 2016 में दोहा पहुंचे थे।
- इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर विचार-विमर्श किया।
- उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल की क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा करते हुए पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

- भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है जिसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) खरीदेगा।ध्यान रहे, कतर, भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है। भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर की हिस्सेदारी 41% है।
- भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (PLL) ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा।

भारत-कतर संबंध

- दोनों देशों के बीच इस वक्त करीब 20 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- भारत को क़तर के लिये चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत का निर्यात 16.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 के 29.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत द्वारा कतर को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद चावल, आभूषण और सोना हैं।
- वहीं पिछले कतर द्वारा किया गया निर्यात 19% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 के 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कतर द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद पेट्रोलियम गैस, क्रूड पेट्रोलियम और हलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं।
- भारत और कतर के व्यापार मंडलों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है जो निवेश पर एक संयुक्त कार्यबल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देता है।
- वर्ष 2022 में "भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज" का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है।
- दोनों देश बहुपक्षीय मंचों जैसे अंतर-संसदीय संघ (IPU), एशियाई संसदीय सभा और अन्य मंचो पर एक-दूसरे को सहयोग करते हैं।
- कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण, एक-दूसरे के सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेना और भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाज़ों द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है| ज़ाएर-अल-बहर (Zair-Al-Bahr) भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान हेतु भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (Indian Cultural Centre- ICC) स्थापित किया गया है| यह केंद्र भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। ध्यान रहे, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास, दोहा, और निजी प्रायोजकों के तत्त्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय है।
- भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं और वो यहां के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इन भारतीयों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः 750 मिलियन डॉलर की राशि भेजी जाती है।

आसियान-भारत माल व्यापार समझौता

सुर्खियों में क्यों?

- आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 16-19 फरवरी 2024 तक वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में भारत द्वारा

आयोजित की गई। संयुक्त समिति की पहली दो बैठकें मई और अगस्त 2023 में आयोजित हुई थी।

- इस बैठक में आसियान देशों के प्रतिनिधि अर्थात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ने भाग लिया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। सितंबर 2022 में, दोनों पक्षों ने समझौते को और अधिक व्यापार सुविधाजनक तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से एआईटीआईजीए संयुक्त समिति को इसकी समीक्षा करने का काम सौंपा है।
- समझौते से संबंधित विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों पर बातचीत करने के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति के अंतर्गत कुल आठ उप-समितियों का गठन किया गया है।
- 2022-23 में भारत-आसियान व्यापार बढ़कर 131.58 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर हो गया है। एआईटीआईजीए की समीक्षा से भारत और आसियान के बीच संतुलित और टिकाऊ तरीके से व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों का लक्ष्य 2025 में समीक्षा समाप्त करना है।
- ध्यान रहे, आसियान-भारत माल व्यापार समझौते संयुक्त समिति की चौथी बैठक मई 2024 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित करने की योजना है।

आसियान (ASEAN) के बारे में

- आसियान (ASEAN) का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया-प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था।
- इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।
- आसियान का आदर्श वाक्य 'वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी' है।
- इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है।
- इस संगठन के संस्थापक सदस्य थाईलैंड के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर है। लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया) शामिल हैं।

भारत-आसियान संबंध

- आसियान के साथ भारत के संबंध उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) की नींव के रूप में कार्य करता है।
- भारत और आसियान ने 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 5 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और 15 साल की समिट लेवल की बातचीत आसियान के साथ शेयर की है।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का व्यापार भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। आसियान को भारत का निर्यात कुल निर्यात का 11.28% है।
- भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिये वर्ष 2003 में आसियान-भारत व्यापार परिषद (ASEAN India-Business Council-AIBC) की स्थापना की गई थी।
- आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिये वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम को दिल्ली संवाद (Delhi Dialogue) कहा जाता है।

INDUS-X शिखर सम्मेलन

सुर्खियों में क्यों?

- 20-21 फरवरी, 2024 को रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास के रूप में INDUS-X शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

INDUS-X के बारे में

- भारत-अमेरिका डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम, जिसे INDUS-X के नाम से भी जाना जाता है, को जून 2023 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था।
- इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग (DoD) के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) द्वारा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और

सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के संयोजन में किया जाता है।

- इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन एक दो दिवसीय कार्यक्रम है जो उभरते अवसरों का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाता है।
- शिखर सम्मेलन में सहयोग, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियों की एक गतिशील श्रृंखला पेश की गई है।
- यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करता है। यह अंतर-राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क को उत्तेजित करता है और घरेलू उद्यमियों, बाजारों, कौशल संस्थानों, सरकारी प्रयोगशालाओं और निवेश पूंजी के बीच संपर्क का मुद्दा बनाता है, जो सफल नवाचार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।

रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस की उपस्थिति में नई दिल्ली में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया।
- इस वर्ष कार्यक्रम का थीम "Chaturanga : Conflict, Contest, Cooperate, Create" है जो चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं और अशांति के साथ-साथ साझेदारी के माध्यम से अवसरों को भी समाहित करता है।

रायसीना डायलॉग क्या है?

- रायसीना डायलॉग भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय

और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation- ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

- इसका प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। 2016 में लॉन्च होने के बाद से यह भारत के सबसे हाई-प्रोफाइल भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मंच के रूप में उभरा है।
- यह यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
- रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिये नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रति वर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है।

प्रयास
IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC
prayasiasacademy
prayasiasacademy
prayasiasacademy.com

By
MUKESH SAHAY
Most Trusted Name For History Optional In India With 27 Years Of Experience
HISTORY OPTIONAL
FOUNDATION COURSE
• English Medium • Hindi Medium
ADMISSION OPEN
upto 50% OFF*
More info Call us:
8818810183 | 8818810184

डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन-2023

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन (डीपीबीएच-2023) के इंटर-कॉलेज प्रतियोगिता राउंड 3 ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में 50 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों से 500 से अधिक छात्रों सहित आईआईटी और एनआईटी के 150 विशेषज्ञों और जूरी सदस्यों ने भाग लिया।
- ध्यान रहे, 15 मार्च, 2024 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर इस प्रभावशाली कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों की उपलब्धियों का जश्न मनाएगा और डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाएगा।
- यह कार्यक्रम एक अग्रणी पहल है, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान सफलतापूर्वक तैयार किया है।
- गौरतलब है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा यह हैकथॉन 26 अक्टूबर 2023 को भ्रामक ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर कार्य करने की दिशा में लोगों को जागरुक करने के निरंतर प्रयास के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इस हैकथॉन का उद्देश्य इनोवेटिव ऐप या सॉफ्टवेयर-आधारित समाधानों को डिजाइन और प्रोटोटाइप करना है जैसे कि ब्राउज़र एक्सटेंशन, प्लगइन्स, ऐड-ऑन, मोबाइल एप्लिकेशन आदि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डार्क पैटर्न के उपयोग, प्रकार और पैमाने की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं।

डार्क पैटर्न क्या होता है?

- डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये मनाने या ऐसे कार्य जो व्यवसायों के लिये फायदेमंद नहीं हों, उन्हें हतोत्साहित करने हेतु उपयोग की जाने वाली रणनीति है।
- इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 2010 में एक यूज़र एक्सपीरियंस (UX) डिज़ाइनर, हैरी ब्रिग्नुल द्वारा किया गया था।
- इस पैटर्न में अधिकतर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हुए अनुचित तात्कालिकता, जबरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाई जाती है।

'वायु शक्ति-24' अभ्यास

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में 'वायु शक्ति-24' अभ्यास का आयोजन किया गया।
- इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायु सेना ने अपनी मारक क्षमता के रोमांचक और दुर्जेय प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- इस वर्ष के अभ्यास का विषय, **'आकाश से बिजली का प्रहार'** को ध्यान में रखते हुए, 120 से अधिक विमानों ने दिन के साथ-साथ रात में भी भारतीय वायु सेना की आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- अभ्यास के दौरान राफेल, SU-30 MKI, मिग-29, मिराज-2000, तेजस और हॉक सहित भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने प्रदर्शन किया।

- इसके आलावा एमआई-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा शामिल गरुड़ ने आतंकवाद रोधी / उग्रवाद रोधी अभियानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक 'अर्बन इंटर्वेंशन' चलाया, जिसका उद्देश्य शत्रु तत्वों के ठिकानों को साफ़ करना था।
- रात के कार्यक्रमों में पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।

GSLV-F14/INSAT-3DS मिशन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 17 फरवरी, 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जीएसएलवी-एफ14 प्रक्षेपण यान द्वारा उपग्रह इन्सैट-3डीएस (INSAT-3DS) को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इन्सैट- 3डीएस वर्तमान में संचालित INSAT-3D तथा INSAT-3DR इन-ऑर्बिट उपग्रहों के साथ देश की मौसम संबंधी (मौसम, जलवायु और महासागर संबंधी) सेवाओं को बढ़ाएगा।
- INSAT 3DR का प्रमोचन वर्ष 2016 में INSAT-3D के अनुवर्ती मिशन के रूप में किया गया था जिसका प्रमोचन वर्ष 2013 में किया गया था।
- नए लॉन्च किए गए इन्सैट-3डीएस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की निगरानी को बढ़ाना, डेटा संग्रह एवं प्रसार तथा उपग्रह-सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाओं में क्षमताओं को बढ़ाना है।
- यह पहल भारत के मौसम, जलवायु और महासागर से संबंधित टिप्पणियों और सेवाओं को बढ़ावा देगी, ज्ञान का विस्तार करेगी और भविष्य में बेहतर आपदा शमन और तैयारियों को और अधिक बढ़ावा देगी।
- इस उपग्रह का वजन 2,275 किलोग्राम है ।
- INSAT-3DS को संवर्धित मौसम विज्ञान प्रेक्षणों, मौसम के पूर्वानुमान में सहायता और आपदा चेतावनी क्षमताओं में सुधार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह पूर्ण रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा वित्तपोषित है तथा भूस्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का एक अनुवर्ती मिशन है।

- INSAT-3DS में चार पेलोड/नीतभार शामिल हैं -
  - ❖ इमेजर पेलोड : INSAT-3DS में एक मल्टी-स्पेक्ट्रल इमेजर है जो छह तरंग दैर्ध्य बैंड में पृथ्वी का प्रतिबिंब उत्पन्न करने में सक्षम है।
  - ❖ साउंडर पेलोड : इसमें 19-चैनल साउंडर पेलोड है जो तापमान और आर्द्रता जैसे वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल प्रदान करता है।
  - ❖ डेटा प्रसारण प्रेषानुकर (Data Relay Transponder-DRT) : DRT के माध्यम से INSAT-3DS स्वचालित मौसम स्टेशनों और डेटा संग्रह प्लेटफार्मों से वैश्विक मौसम विज्ञान, जल विज्ञान एवं समुद्र संबंधी डेटा प्राप्त करता है तथा इसका प्रसारण पुनः उपयोगकर्त्ता टर्मिनलों पर करता है।
  - ❖ उपग्रह साधित खोज एवं बचाव प्रेषानुकर (Satellite-Aided Search and Rescue Transponder : SA&SR के माध्यम से INSAT-3DS अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को कवर करते हुए वैश्विक खोज और बचाव सेवाओं के लिये संकट संकेतों को प्रसारित करता है।

i-ऑन्कोलॉजी AI प्रोजेक्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने "i-ऑन्कोलॉजी AI प्रोजेक्ट" नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित मॉडल विकसित किया है जिसमें एक सुपर कंप्यूटर एकीकृत किया गया है।
- यह मॉडल ऑन्कोलॉजिस्टों को कैंसर के उपचार के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करेगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस प्रोजेक्ट को AIIMS, दिल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), पुणे तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त प्रयसों द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य AI का उपयोग कर कैंसर के उपचार की सटीकता और प्रभावकारिता बढ़ाना है और साथ ही आनुवंशिक प्रोफाइल, नैदानिक इतिहास और उपचार परिणामों को शामिल करने वाले व्यापक डेटासेट का विश्लेषण कर आनुवंशिकी तथा कैंसर चिकित्सा की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करना है।
- यह प्लेटफॉर्म रक्त परीक्षण, लैब रिपोर्ट, स्कैन एवं रोगी के रिकॉर्ड सहित कैंसर से संबंधित विभिन्न डेटा को संग्रहीत करने के साथ-साथ विश्लेषण भी करता है।
- उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, AI-सक्षम प्लेटफॉर्म डॉक्टरों को व्यापक जीनोमिक डेटा विश्लेषण के आधार पर उपचार निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे रोगियों के लिये उपचार योजना तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है।
- भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट तथा डिम्बग्रंथि कैंसर की व्यापकता को देखते हुए, i-ऑन्कोलॉजी, AI का प्रारंभिक अनुप्रयोग इन कैंसर का शीघ्र पता लगाने पर केंद्रित है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है | इस दिवस का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु जनजागरूकता फैलाना है।

- गौरतलब है कि 2 फरवरी, 1971 को रामसर समझौते (Ramsar Convention) पर हस्ताक्षर किये गए थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस-2024 का विषय **'आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण'** है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमि बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता और मनोरंजन के अवसरों में योगदान करती हैं, जो मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का जश्न मनाने के लिए इंदौर नगर निगम और पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन (ईपीसीओ), मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से सिरपुर झील, इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 पर, भारत ने पांच और आर्द्रभूमियों को रामसर साइटों के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइटों (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) की संख्या को बढ़ाकर 80 तक कर दी है। इनमें से तीन स्थल, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि दो, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में हैं।

आर्द्रभूमियों का महत्त:

- नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि (Wetland) कहा जाता है। वस्तुत: आर्द्रभूमियों से भोजन, पानी, रेशा (फाइबर), भूजल का पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, भूमि के कटाव का नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों और इको-सिस्टम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त होती हैं।
- जलीय निकाय और स्थल क्षेत्र के मिलन वाली जगहों पर आर्द्रभूमियां पायी जाती हैं। आर्द्रभूमियों में, मैंग्रोव और कच्छ भूमि, पीटलैंड, नदियाँ, झीलें और अन्य जलीय निकाय, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और वन क्षेत्रों में दलदली भूमि, धान के खेत और प्रवाल भित्तियां आदि शामिल होते हैं।
- विश्व की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमियों में निवास करती हैं अथवा इनमें प्रजनन करती हैं। इसलिए आर्द्रभूमियों को 'जीवन की नर्सरी' कहा जाता है।
- आर्द्रभूमियां 'पृथ्वी के फेफड़े' होती हैं जो वातावरण से प्रदूषकों को साफ करते हैं। आर्द्रभूमियां 'जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण' होती हैं। ये 30% भूमि आधारित कार्बन का भंडारण करती हैं।
- आर्द्रभूमियां 'आपदा जोखिम को कम करती हैं'। ये तूफानों के वेग को अवरुद्ध करती हैं।

समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोटेश्वर (कोरी क्रीक), कच्छ, गुजरात में किया गया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री उत्पादन में विविधता लाने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिये समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है।

समुद्री शैवाल क्या हैं?

- समुद्री शैवाल स्थूल, बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल हैं। वे लाल, हरे और भूरे सहित विभिन्न रंगों के होते हैं। इन्हें '21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन' कहा जाता है।
- समुद्री शैवाल अधिकतर अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में, समुद्र के उथले और गहरे पानी में व मुहाना तथा बैकवाटर में भी पाए जाते हैं।
- भारत के समुद्रों में लगभग 844 समुद्री शैवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रचुर मात्रा में समुद्री शैवाल तमिलनाडु और गुजरात तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाए जाते हैं।

नोखरा सौर परियोजना का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावॉट की नोखरा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किये।

संबंधित प्रमुख तथ्य

- राजस्थान के बीकानेर जिले में 1,550 एकड़ में फैली यह परियोजना 1,803 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीपीएसयू योजना (चरण- II) के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
- प्रति वर्ष 73 करोड़ यूनिट के उत्पादन के साथ यह परियोजना न केवल 1.3 लाख से अधिक घरों को रोशन करेगी, बल्कि हर साल 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को सीमित करने में भी मदद करेगी। आगे चलकर इस परियोजना की मदद से 25 वर्षों की अवधि में CO_2 उत्सर्जन को 15 मिलियन टन तक सीमित करने की उम्मीद है।
- सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस परियोजना में 13 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं। इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी।

एनटीपीसी के बारे में

- एनटीपीसी लिमिटेड 74 गीगावॉट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली ईकाई है जो भारत में उत्पादित कुल बिजली का 25% योगदान देती है।
- ध्यान रहे, वर्ष 2032 तक एनटीपीसी अपनी गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली क्षमता को कंपनी के पोर्टफोलियो के 45%-50% तक विस्तार देना चाहता है। इसमें 130 गीगावॉट के कुल पोर्टफोलियो के साथ 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल होगी।
- एनटीपीसी ने भारत के नेट जीरो प्रयासों को मजबूती देने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की है।
- एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका लक्ष्य एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना है। इसकी परिचालन ग्रीन एनर्जी कैपिसिटी 3.4 गीगावॉट से अधिक है और 26 गीगावॉट प्रक्रिया में है, जिसमें 7 गीगावॉट का परिचालन शुरू होने वाला है।

भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति

- नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है।
- दिसंबर 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 180.79 गीगावॉट है जिसमें सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 73.31 गीगावॉट हो गई है।
- ध्यातव्य रहे, भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता के लिए 500 गीगावॉट का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- जून 2022 तक राजस्थान और गुजरात बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले शीर्ष राज्य थे। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।

जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा के कोरापुट ज़िले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) घोषित किया गया है। इससे पहले ओडिशा के तीन क्षेत्रों मंदसरू, महेंद्रगिरि और गंधमर्दन को जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) के रूप में घोषित किया गया है।
- यह वन 350 हेक्टेयर के सीमांकित क्षेत्र को कवर करता है और जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय अपने पवित्र उपवनों के साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्त्व है।
- यह वन स्तनधारियों की 28 प्रजातियों सहित कम-से-कम 608 जैव प्रजातियों का निवास स्थान है। इन प्रजातियों में मगरमच्छ, कांगेर घाटी रॉक गेको, सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग और विभिन्न पक्षी जैसे काला बाजा, जेर्डन बाजा, मालाबेर ट्रोगोन, आम पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाले कठफोड़वा और बैंडेड बे कोयल शामिल हैं।

जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) क्या है?

- जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे, सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैवविविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ-साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त, कीस्टोन प्रजाति पाई जाती हैं।
- जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय-समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैवविविधता के महत्त्व के क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
- जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) के निर्माण से स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर उनके द्वारा स्वेच्छा से तय की गई प्रथाओं के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैवविविधता विरासत स्थल था, जिसे वर्ष 2007 में जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 जैवविविधता विरासत स्थल मौजूद हैं।

CMS के पक्षकारों का 14वाँ सम्मेलन (COP-14)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS 14) के लिये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (CoP) की चौदहवीं बैठक का आयोजन समरकंद, उज़्बेकिस्तान में किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- बैठक में पक्षकारों ने 14 प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के संबद्ध में लिस्टिंग/सूचीबद्धता प्रस्तावों को अपनाने पर सहमति जताई ।

- इन प्रवासी प्रजातियों में यूरेशियन लिंक्स, पेरूवियन पेलिकन, पल्लास की बिल्ली, गुआनाको, लाहिले की बॉटलनोज़ डॉल्फिन, हार्बर पोरपोइज़, मैगेलैनिक प्लोवर, बियर्डेड वल्चर, ब्लैकचिन गिटारफिश, बुल रे, लुसिटानियन काउनोस रे, गिल्डेड कैटफिश और लौलाओ कैटफिश शामिल हैं।
- प्रस्तावों में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी खतरों का समाधान करने, शोध करने और संरक्षण नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये रेंज राज्यों (Range States) के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया। विदित है कि रेंज राज्य का आशय उन देशों अथवा क्षेत्रों से है जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं जहाँ एक विशेष प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ये देश अथवा क्षेत्र प्रजातियों और उनके आवास के प्रबंधन, संरक्षण तथा सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।
- बैठक में प्रवासी प्रजातियों के मौजूदा विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें निवास स्थान का क्षरण, विखंडन, अवैध व्यापार, बायकैच, संदूषक और कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे फेंसिंग, तेल तथा गैस हेतु पर्यावरण का ह्रास, खनन एवं जल के भीतर ध्वनि जैसी मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं।

CMS क्या है?

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
- इस संधि पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह वर्ष 1983 से लागू है। 1 मार्च 2022 तक CMS में 133 पार्टियाँ/राष्ट्र सम्मिलित हुए हैं। भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक सदस्य रहा है।
- इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिये कानूनी आधार तैयार करता है।
- CMS के अंतर्गत दो परिशिष्ट - परिशिष्ट I (संकटापन्न प्रवासी प्रजातियाँ) और परिशिष्ट II ('अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों') की सूची दी गई है।
- CMS के अंतर्गत भारत ने कुछ प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये गैर-बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर भी किये हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डूगोंग (2008) और रैप्टर (2016) शामिल हैं।
- गौरतलब है कि भारत, विश्व के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्विक जैवविविधता में लगभग 8% का योगदान देता है। भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है जिनमें अमूर फाल्कन, बार-हेडेड गीज़, ब्लैक-नेक्ड क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, हंपबैक व्हेल आदि शामिल हैं।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र प्रायोजित योजना यानी "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र

कार्यक्रम" को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव को कुल 4,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के दो घटक हैं -
  - ❖ कुल 2940 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ FMBAP के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) वाले घटक के तहत बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी व्यवस्था के विकास और समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के राज्यों में किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त प्रबंधन 60 प्रतिशत (केन्द्र) और 40 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण पद्धति 90 प्रतिशत (केंद्र) और 10 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में रहेगी।
  - ❖ कुल 1160 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ FMBAP के नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के तहत पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमा पर स्थित साझी नदियों पर जल विज्ञान संबंधी अवलोकन एवं बाढ़ के पूर्वानुमान सहित बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव-रोधी कार्यों और सीमा पर स्थित साझी नदियों पर संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं की जांच व निर्माण-पूर्व गतिविधियों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ शामिल किया जाएगा।
- ध्यान रहे, बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाढ़ प्रबंधन में राज्य

सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देना, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवीन सामग्री/दृष्टिकोण को बढ़ावा देने व अपनाने को प्रोत्साहित करना वांछनीय है।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के बारे में

- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme FMBAP) को मंज़ूरी दी थी।
- इस कार्यक्रम को बाढ़ प्रबंधन कार्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा कार्यों हेतु पूरे देश में लागू किया गया है।
- FMBAP योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) तथा नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (River Management Activities and Works related to Border Areas-RMBA) नामक दो स्कीमों के घटकों को आपस में विलय करके तैयार की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, भू-क्षरण पर नियंत्रण के साथ-साथ समुद्र तटीय क्षेत्रों के क्षरण के रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
- यह योजना देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गाँवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचों आदि को बचाने में मदद करेगा। साथ ही जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं जैसे- नेपाल में पंचेश्वर तथा सप्तकोसी सनकोसी परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जाँच-पड़ताल एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि तैयार करना भी शामिल है।

महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात के मोरबी में स्वामी दयानंद के जन्मस्थान टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।

महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में

- दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को टंकारा, गुजरात में मूल शंकर के रूप में करशनजी लालजी तिवारी और यशोदाबाई के घर हुआ था। परिवार अत्यधिक धार्मिक होने के कारण, मूल शंकर को बहुत कम उम्र से ही धार्मिक अनुष्ठान, धर्मपरायणता और पवित्रता, उपवास का महत्व सिखाया गया था।

- महर्षि दयानंद हिंदू धर्म में आस्तिक थे, उन्होंने धर्म की अवधारणाओं की पुरजोर वकालत की, जिसे वे किसी भी पक्षपात से मुक्त और सत्यता का प्रतीक मानते थे।
- वे मूर्ति पूजा की प्रथा, अंधविश्वास और जाति अलगाव जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे।
- उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा की वकालत की, जिसका अर्थ है विदेशी प्रभाव से मुक्त, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रतिभागियों की महिमा से भरपूर देश।
- 7 अप्रैल, 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज का उद्देश्य हिन्दू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर करना था। 'कृण्वं से विश्वं आर्यम्' इसका आदर्श वाक्य था, जिसका अर्थ है, "इस दुनिया को महान बनाओ"।
- आर्य समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, मंदिरों में चढ़ावा, पुरोहिताई को प्रायोजित करने आदि जैसी कर्मकांडीय प्रथाओं की निंदा करने का निर्देश देता है। समाज ने अनुयायियों को मौजूदा मान्यताओं और रीति-रिवाजों पर आंख मूंदकर उनका पालन करने के बजाय उन पर सवाल उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
- आर्य समाज ने 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। महर्षि दयानंद ने बालिका शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया और बाल विवाह का विरोध किया।
- शुद्धि आंदोलन महर्षि दयानंद द्वारा उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था जो या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। शुद्धि या शुद्धिकरण उन लोगों को प्रदान किया गया जो हिंदू धर्म में वापस आने का रास्ता तलाश रहे थे और समाज ने समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश करने और दलित वर्गों को हिंदू धर्म में वापस लाने में उत्कृष्ट काम किया।
- उन्होंने अपने अनुयायियों को वेदों का ज्ञान सिखाने और ज्ञान को और अधिक फैलाने के लिए कई गुरुकुल स्थापित किए। उनके विश्वासों, शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर, उनके शिष्यों ने 1883 में उनकी मृत्यु के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। पहला डीएवी हाई स्कूल 1 जून 1886 को लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके हेडमास्टर लाला हंस राज थे।

आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी का निधन

सुर्खियों में क्यों?

- 18 फरवरी, 2024 को जैन धर्म के दिगंबर मुनि एवं महान संत परमपूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए है| उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चन्द्रगिरि तीर्थ में समाधि ली।
- विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को पूर्णिमा उत्सव (शरद पूर्णिमा) के दौरान कर्नाटक के बेलगाम जिले के सदलगा में एक कन्नड़ भाषी जैन परिवार में हुआ था।
- उन्होंने आम तौर पर अपना अधिकांश समय बुंदेलखण्ड क्षेत्र में बिताया जहां उन्हें शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों में पुनरुत्थान लाने का श्रेय दिया जाता है। 1972 में विद्यासागर को आचार्य का दर्जा दिया गया था।
- आचार्य विद्यासागरजी संस्कृत और प्राकृत के विद्वान थे और हिंदी, कन्नड़ , मराठी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हाइकु कविताएँ और महाकाव्य हिंदी कविता "मुकामाती" लिखी।
- जैन धर्म में आचार्य शब्द का अर्थ होता है मुनि संघ के नायक। दिगम्बर संघ के कुछ अति प्रसिद्ध आचार्य हैं- भद्रबाहु, कुन्दकुन्द स्वामी, आचार्य समन्तभद्र, आचार्य उमास्वामी। दिगम्बर परम्परा में आचार्य के 36 प्राथमिक गुण (मूल गुण) बताए गए हैं।

श्री कल्कि धाम मंदिर

सुर्खियों में क्यों?

- 19 फरवरी, 2024 को श्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया।
- इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं।
- इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जहां भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। ये मंदिर विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्कि को समर्पित होगा ।
- कल्कि धाम में भी अयोध्या मंदिर की तरह गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल होगा। खास बात ये है कि इस मंदिर में भी स्टील और लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनायीं जाएगी तथा शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी ।

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

सुर्खियों में क्यों?

- प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उनके साहस, युद्ध रणनीति और प्रशासनिक कौशल को याद करने के लिये मनाई जाती है।

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में

- छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी, 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे ज़िले के शिवनेरी किले में हुआ था।
- उनका जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोंसले के घर हुआ था, जिनके अधिकार में बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरें थीं तथा उनकी माता जीजाबाई एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनके धार्मिक गुणों का उन पर गहरा प्रभाव था।
- उन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए तोरण किले (Torna Fort) तथा बाद में कोंडाना किले (Kondana Fort) पर भी अधिकार कर लिया था।
- ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। उन्होंने बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के पतन के समय इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया, जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया।
- शिवाजी को 6 जून, 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति, शाककार्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी।
- छत्रपति शिवाजी का मुगलों के साथ भी संघर्ष हुआ और इस क्रम में कई युद्ध भी हुए, जिनमें से प्रमुख हैं- सूरत का युद्ध (1664), पुरंदर का युद्ध (1665), सिंहगढ़ का युद्ध (1670), कल्याण का युद्ध (1682-83) एवं संगमनेर का युद्ध (1679) ।
- शिवाजी का 3 अप्रैल, 1680 को रायगढ़ में निधन हो गया और रायगढ़ किले में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

छत्रपति शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था

- शिवाजी दक्कन शैली के आधार पर अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इनका अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर (Malik Amber) के सुधारों से प्रेरित थे।
- राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा होता था जिसे 'अष्टप्रधान' के नाम से जाना जाता है। उन्हें आठ मंत्रियों के एक समूह द्वारा शासन कार्य में सहायता प्रदान की जाती थी।
- पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था।
- शिवाजी का राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली (Kathi System) से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था।
- उन्होंने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रणाली को अपनाया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था।

- चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था जिसे गैर-मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का 10 प्रतिशत होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था।
- शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। मराठा सेना में इन्फैंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थीं।
- सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान (सरंजम या मोकासा) के माध्यम से भुगतान किया जाता था।

सम्मक्का-सरक्का मेदारम जथारा त्योहार

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 21 फरवरी, 2024 को एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला सम्मक्का -सरक्का जथारा तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू हुआ। चार दिवसीय मेदाराम जथारा उत्सव कन्नेपल्ली गांव से सरक्का की मूर्ति के पारंपरिक आगमन के साथ शुरू हुआ।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- सम्मक्का सरक्का जथारा, जिसे मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है, देवी-देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है।
- मेदाराम जतारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला और एशिया के सबसे बड़े जनजातीय मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय- कोया जनजाति द्वारा चार दिनों तक मनाया जाता है।

- यह मेदाराम जथारा देवी सम्मक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह दो साल में एक बार 'माघ' (फरवरी) महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
- यह शासक शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माँ और बेटी, सम्मक्का और सरक्का की लड़ाई की याद दिलाता है। सरलाम्मा सम्मक्का की बेटी थी। उनकी मूर्ति, अनुष्ठानों के अनुसार, मेदाराम के पास एक छोटे से गाँव कन्नेपल्ली के एक मंदिर में स्थापित की गई है।
- सम्मक्का की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। एक आदिवासी कहानी के अनुसार, लगभग 6-7 शताब्दी पहले, 13वीं शताब्दी में, शिकार करने गए कुछ आदिवासी नेताओं को एक नवजात लड़की (सम्मक्का) मिली जो बाघों के बीच खेल रही थी और भारी रोशनी छोड़ रही थी। वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए, और जनजाति के मुखिया ने उसे सरदार के रूप में अपनाया। बाद में वह इलाके के आदिवासियों की रक्षक बन गईं।
- उनका विवाह काकतीय के एक सामंती आदिवासी प्रमुख पागिदिद्दा राजू से हुआ था, जिन्होंने 1000 ईस्वी और 1380 ईस्वी के बीच वारंगल शहर से आंध्र प्रदेश पर शासन किया था।

संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। गौरतलब है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, संत रविदास जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और संत रविदास संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी।
- गुरु रविदास का जन्म 1377 ई. में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में साधारण परिवार से हुआ था।
- गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक हैं।
- वाराणसी में वंचित अछूत चमड़े का काम करने वाली जाति में जन्मे, उनका जीवन और कार्य उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की चुनौतियों और संघर्षों को गहराई से दर्शाते हैं।

पांच व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में डॉ. एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर एवं लालकृष्ण आडवानी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई।

संबंधित प्रमुख तथ्य

- डॉ. एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण दिया गया है। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है।
- प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिह्नित किया गया था जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह वीपी सिंह के साथ यूपी के केवल दो मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, जो पीएम बने। चौधरी चरण सिंह किसानों के हितों में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं।
- लालकृष्ण आडवानी अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे जबकि अटल सरकार में जून 2002 से मई 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा भी किये थे।
- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार दलितों के उत्थान, वंचित वर्गों के सशक्तीकरण और समानता, भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को मजबुती प्रदान करने हेतु दिया गया है।

भारत रत्न के बारे में

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है।
- इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती हैं।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक हो सकती है।

SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) की अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप का आयोजन ढाका में किया गया।
- 8 फरवरी 2024 को ढाका में खेले गए फाइनल में इस चैम्पियनशिप का विजेता भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से घोषित किया गया।
- दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की एक क्षेत्रीय सहायक कंपनी है।
- SAFF की स्थापना 1997 में किया गया था। इस संघ के 7 सदस्य हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024

सुर्खियों में क्यों?

- 19 फरवरी, 2024 को केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथा संस्करण का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- ध्यान रहे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में ओडिशा में, दूसरा संस्करण वर्ष 2022 में बंगलूरू, कर्नाटक में तथा तीसरा संस्करण वर्ष 2023 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था।
- उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से पूर्वोत्तर के सात राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को संबोधित करते हुए इस गेम्स के शुभंकर यानी तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख किया। इन खेलों में तितली को शुभंकर बनाना इस बात का भी प्रतीक है कि पूर्वोत्तर को कैसे नया अनुभव मिल रहा है।"
- मोदीजी अपने संबोधन में वर्तमान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आलावा लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दीव में बीच गेम्स का भी उल्लेख किया।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह चौथा संस्करण है जिसमें देश भर के 4544 एथलीट भाग लेंगे। इस संस्करण में एथलेटिक्स, रग्बी, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल सहित 20 खेल विधाओं को शामिल किया है। इसके अलावा फिट इंडिया को बढ़ावा देने के मिशन के हिस्से के रूप में, योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भी इवेंट लाइन-अप में शामिल किया गया है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में

- खेलो इंडिया अर्थात् 'लेट्स प्ले इंडिया' को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर विद्यार्थियों के साथ जुड़कर भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित है|
- इस कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) और खेलो इंडिया विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित किया गया।
- इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक खेल विधाओं को पुनर्जीवित करना है तथा विभिन्न खेलों के लिये देश भर में बेहतर खेल संरचना एवं अकादमियों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
- खेलो इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के प्रस्ताव के अनुरूप पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेल को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसी के तर्ज पर वर्ष 2018 में मणिपुर के इम्फाल में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
- खेलो इंडिया पूरे भारत में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की स्थापना का भी समर्थन करता है, जिसे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (KISCE) कहा जाता है। इन केंद्रों का उद्देश्य क्षमतावान खिलाड़ियों के लिये आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना और प्रत्येक खिलाड़ी में खेल संबंधी अनुशासन को बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रयास करना है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अभ्यास मिलन 2024 के एक भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन अभ्यास मिलन 2024 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह महासागरों के पार स्थित देशों के बीच सहयोग, तालमेल एवं विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।
- इस सम्मेलन में भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष, मैत्रीपूर्ण संबंध वाले देशों के नौसेना प्रमुखों, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, भारत तथा मित्रवत देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति ने समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर किया है।

- इस सम्मेलन की विषय-वस्तु **"महासागरों में साझेदार: सहयोग, तालमेल, विकास,"** पर विभिन्न प्रस्तुतियों और चर्चाओं की एक शानदार श्रृंखला पेश की गई।
- यह प्रस्तुति आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन शमन, नीली अर्थव्यवस्था पहल और समुद्र आधारित बुनियादी ढांचे के सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित थे।
- यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों को हल करने और उपलब्ध अवसरों को इस्तेमाल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्थायी महत्व के प्रमाण के रूप में सामने आया है।
- इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों ने सार्थक संवाद और साझेदारी के माध्यम से अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं समृद्ध समुद्री क्षेत्र के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया है।

अभ्यास मिलन 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 16 से 27 फरवरी के दौरान विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 'मिलन- 2024' का आयोजन किया गया।
- यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा आयोजित किया गया।
- यह नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण है जो दो चरणों में आयोजित हुआ, पहला- बंदरगाह में एवं दूसरा समुद्र में। अभ्यास का बंदरगाह चरण 19 से 23 फरवरी तक जबकि समुद्री चरण 24 से 27 फरवरी तक आयोजित किया गया।
- इस संस्करण में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलयेशिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं।

अभ्यास 'मिलन' क्या है?

- मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका मकसद समान विचारधारा वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसकी शुरुआत 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में भारतीय नौसेना द्वारा केवल चार देशों, अर्थात इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ हुआ था।
- यह पहल मूल रूप से भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप है, लेकिन आने वाले वर्षों में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और सागर पहल के साथ विस्तार किया, जिसमें पश्चिमी आईओआर (हिंद महासागर क्षेत्र) में द्वीप राष्ट्रों के साथ-साथ आईओआर तटीय क्षेत्रों की भागीदारी भी शामिल की गई।

58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में ज्ञानपीठ चयन समिति ने घोषणा की कि वर्ष 2023 के लिये 58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लेखकों, संस्कृत विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य तथा उर्दू कवि और गीतकार गुलज़ार को दिया जाएगा।

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह किसी लेखक को उनके "साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान" के लिये प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- यह पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित एवं पहली बार वर्ष 1965 में प्रदान किया गया था।
- यह पुरस्कार अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिये प्रदान किया जाता करता है। हालाँकि अर्हता भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है।
- यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिये दिया जाता है।

- ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पट्टिका और देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिकृति शामिल है।
- आज तक, महादेवी वर्मा, सुब्रमण्यम भारती, अमृता प्रीतम, यूआर अनंतमूर्ति आदि जैसे दिग्गजों सहित 58 साहित्यिक दिग्गजों को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च साहित्यिक मान्यता प्रदान की गई है।

भारत टेक्स 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 26 फरवरी से शुरू होने वाले भारत टेक्स 2024 चार दिवसीय कार्यक्रम है जिसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत टेक्स अपने विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ नई दिल्ली में दो स्थानों भारत मंडपम और यशोभूमि में 22 लाख वर्ग फुट से अधिक फैला हुआ है।
- 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खरीदारों की भागीदारी और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की उपस्थिति के साथ, यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम है।
- इस आयोजन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सहित 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- भविष्य के सर्कुलर समाधानों की पहचान के लिए टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जाएगा।
- यह आयोजन 11 निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सभी मूल्य श्रृंखला दिग्गजों के बीच सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है, जो फार्म से लेकर अंतिम उत्पादों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।
- भारत टेक्स प्रदर्शनी में परिधान, घरेलू सामान, फर्श कवरिंग, फाइबर, सूत, धागे, कपड़े, कालीन, रेशम, कपड़ा आधारित हस्तशिल्प, तकनीकी कपड़ा और बहुत कुछ शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 5एफ विजन से प्रेरित होकर इस कार्यक्रम का 'एकीकृत फार्म टू फैशन फोकस', संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य : एक नजर में

- भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नंद किशोर यादव पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सात बार विधान सभा सदस्य (MLA) थे। इससे पूर्व बिहार विधानसभा का अध्यक्ष राजद नेता अवध बिहारी चौधरी थे ।
- हाल ही में देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित है और पटना के गर्दनीबाग में स्थित है। यह टावर 120 फीट लंबा है और इसमें छह मंजिलें हैं। टावर में अहमदाबाद में तैयार की गई मूर्तियों और कलाकृतियों के साथ गांधी के इतिहास और बिहार से संबंधित एक प्रदर्शनी भी शामिल है।
- हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए डिवाइस 'NITISH' लॉन्च किया है। यह डिवाइस बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। यह डिवाइस उपयोगकर्ताओं को आसन्न बिजली, बाढ़, लू और शीत लहर के बारे में सचेत करने के लिए ध्वनि संदेशों का उपयोग करता है, जिससे किसानों और आम लोगों को सूचित और संरक्षित रहने में मदद मिलती है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए, देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के मुहम्मद हुसैन को कला एवं संस्कृति के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
- नीति आयोग के "राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे अमीर राज्य केरल है। 5 जनवरी, 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान (2013-14 से 2022-23 के मध्य) उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
- वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में प्रस्तुति देने के लिए बिहार के लोक नृत्य झिझिया का चयन किया गया था।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बिहार के मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा और कटिहार समेत 12 राज्यों में 26 एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया।
- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव (International Buddhist Festival) 2024 का आयोजन बिहार के बोधगया के कालचक्र मैदान में किया गया।
- मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में 591 करोड़ रू० की लागत से श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकार्पण किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल में सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- 2024 में बिहार के एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, एक व्यक्ति को पद्म भूषण और चार व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सहित कुल 6 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है । इसमें से श्री विन्देश्वेरी पाठक को मरणोपरांत सामाजिक कार्य हेतु पद्म विभूषण पुरस्कार, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्मभूषण पुरस्कार तथा श्री अशोक कुमार विश्वास (कला), श्री सुरेन्द्र किशोर (साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता), श्री राम कुमार मल्लिक (कला) और सुश्री शांति देवी पासवान एवं श्री शिवन पासवान (कला) को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स 2023-24 के 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार की बेटी दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही दुर्गा ने 4:29:22 मिनट में दौड़ पूरी कर पिछला रिकार्ड तोड़ते हुए खेलो इंडिया गेम्स का नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है।
- पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री एवं 68 वर्षीय आसिफ जरदारी फिर से देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ 2022 से 2023 तक प्रधानमंत्री रहे जबकि आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे।
- 21 फरवरी, 2024 को, फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारतीय संसद सदस्य और लेखक शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान 'शेवेलियर डे ला लीजियन डी'ऑनूर' (नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) से सम्मानित किया। डॉ. थरूर एक प्रशंसित लेखक, पूर्व राजनयिक और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबद्ध सांसद हैं जो लोकसभा में तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी, 2024 को घोषणा की कि छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली वार्षिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में दो बार उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा। इस सुधार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप परीक्षा तनाव को कम करना है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में पीएम श्री (प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना भी लॉन्च की, जिसके तहत राज्य के 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने हर साल स्कूल में 10 बैग-रहित दिन शुरू करने की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला और छात्रों को अन्य गतिविधियों के अलावा कला, संस्कृति और खेल से जोड़ने पर जोर दिया।

- स्टार भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट के साथ अनिल कुंबले के बाद कुल नौवें गेंदबाज बनकर और भारत के दूसरे गेंदबाज बनकर क्रिकेट रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
- 18 फरवरी 2024 को, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिलाओं ने रोमांचक फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराया। यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत का पहला खिताब था, पुरुष टीम ने इससे पहले 2016 और 2020 में दो कांस्य पदक जीते थे।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day) 21 फरवरी को मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 की थीम है "बहुभाषी शिक्षा अंतर-पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है" ("Multilingual education is a pillar of intergenerational learning")। ये थीम पीढ़ीगत शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुभाषी शिक्षा के महत्व पर जोर देता है।
- 17 से 19 फरवरी, 2024 तक ईरान के तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। भारत 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं चीन 6 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।
- 21 फरवरी को रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले रेडियो प्रेजेंटर 'अमीन सयानी' का निधन हो गया। सयानी ने करीब 19 हजार जिंगल्स में अपनी आवाज दी, जिसके लिए उनका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्हें 2006 में लिविंग लीजेंड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। 1991 में गोल्ड मेडल, 1992 में पर्सन ऑफ द ईयर अवॉर्ड और 2003 में कान हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड से भी नवाजा गया।
- बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'शांति प्रयास IV' (Shanti Prayas IV) का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे है। शांति प्रयास अभ्यास की सह-मेजबानी नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड द्वारा की जाती है, जो नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को दर्शाता है।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में यूरोपीय देश माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा की राजधानी वैलेटा है। देश में बोली जाने वाली भाषाएँ माल्टीज़ और अंग्रेजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्ष 2015 में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है।
- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के लिए "आरोग्य-डॉक्टर ऑन व्हील्स" पहल शुरू की गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा संचालित एक टेली क्लिनिक है, इससे जम्मू कश्मीर के दूर-दराज में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- 19 फरवरी, 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) तथा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा धारणीयता एवं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के जरिए इरेडा और पीएनबी एक-दूसरे के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेय लोगों को रोजगार के अवसर देने हेतु "हिमालयन बास्केट" का शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। दोनों ने डेयरी, खेती और उनके पहलुओं से संबंधित विकल्पों पर विचार कर हिमालयन बास्केट की स्थापना का निर्णय लिया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया।
- लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने 19 फरवरी 2024 थल सेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया। थल सेना के उपप्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल में 2022-2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर कार्यरत थे।
- 22-25 फरवरी, 2024 तक भारत-मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास "दोस्ती" का 16वाँ संस्करण का आयोजन किया गया। इस वर्ष पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश भाग लिया।

करेंट अफेयर्स आधारित प्रश्न

1. किस प्रमुख भारतीय संगीतकार ने अपने नवीनतम एल्बम "दिस मोमेंट" के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता?
   (a) ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर
   (b) शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन
   (c) हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति
   (d) सोनू निगम और श्रेया घोषाल
2. झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्वकर्त्ता कौन है?
   (a) हेमंत सोरेन (b) इंद्रजीत महथा
   (c) चंपई सोरेन (d) रामदास सोरेन
3. हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है?
   (a) जर्मनी (b) पुर्तगाल
   (c) इटली (d) फ्रांस
4. विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है ?
   (a) 1 फरवरी (b) 2 फरवरी
   (c) 4 फरवरी (d) 10 फरवरी
5. हाल ही में केंद्र सरकार ने 'लखपति दीदी योजना' के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है?
   (a) 3 करोड़ (b) 3.5 करोड़
   (c) 4 करोड़ (d) 4.5 करोड़
6. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण के लिए आगे बढ़ने वाला नवीनतम राज्य है?
   (a) उत्तर प्रदेश (b) पश्चिम बंगाल
   (c) झारखंड (d) छत्तीसगढ़
7. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जिसे शिव जयंती भी कहा जाता है, मनाई जाती है -
   (a) 18 फरवरी (b) 19 फरवरी
   (c) 20 फरवरी (d) 21 फरवरी
8. हाल ही में खबरों में रहे धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें -
   1. सरकार ने चुनावी बांड पेश करने वाले कानून लाने के लिए धन विधेयक मार्ग का इस्तेमाल किया।
   2. सरकार ने धन विधेयक मार्ग का उपयोग किया, जिसने एक कानून को राज्यसभा की जांच से बचने की अनुमति दी।
   3. भारत के संविधान में धन विधेयक को परिभाषित नहीं किया गया है।

   उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
   (a) केवल एक (b) सिर्फ दो
   (c) सभी तीन (d) इनमे से कोई भी नहीं
9. बीमा सुगम पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. बीमा सुगम IRDAI द्वारा शुरू किया गया महत्वाकांक्षी बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है।
   2. बीमा सुगम एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा या प्रोटोकॉल है जिसमें खुले मानक और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म हैं।
   3. बाज़ार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा।

   उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
   (a) केवल एक (b) केवल दो
   (c) तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
10. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का मुख्यालय स्थित है -
    (a) कोच्चि (b) कोलकाता
    (c) चेन्नई (d) नई दिल्ली
11. अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया?
    (a) रक्षा मंत्रालय (b) शिक्षा मंत्रालय
    (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय (d) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
12. किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है?
    (a) बिहार (b) मध्य प्रदेश
    (c) उत्तर प्रदेश (d) राजस्थान
13. हाल ही में खबरों में देखी गई सुबिका पेंटिंग्स निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
    (a) मध्य प्रदेश (b) बिहार
    (c) असम (d) मणिपुर

1. (b)	2. (c)	3. (d)	4. (b)	5. (a)	6. (c)	7. (b)	8. (b)
		9. (c)	10. (d)	11. (a)	12. (c)	13. (d)	

प्रयास
IAS ACADEMY

PRAYAS IAS ACADEMY INAUGURATION

THANKING PRINT MEDIA

प्रयास आइएएस एकेडमी का हुआ उद्घाटन

प्रयास आइएएस एकेडमी का उद्घाटन करते अतिथि ● सौ : संस्थान

पटना. (वि.): प्रयास आइएएस एकेडमी का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस अवसर महेश्वर हजारी (उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा), हरि सहनी (एमएलसी), जीवन कुमार (एमएलसी), आशुतोष रवि (जज), सीता साहू (मेयर), आमिर सुबहानी (मुख्य सचिव, बिहार सरकार), विकास वैभव (आइजी), प्रत्यय अमृत (आइएएस), अंजनी सिंह (आइएएस), शीला ईरानी (आइपीएस), फिरोज आलम (डीएसपी) व निदेशक राहुल राज मौजूद रहे।

प्रयास आईएएस एकेडमी का शुभारंभ

पटना। प्रयास आईएएस एकेडमी का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस अवसर पर महेश्वर हजारी (उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा), हरि सहनी (विधान पार्षद), जीवन कुमार (विधान पार्षद), आशुतोष रवि (दानापुर जज), सीता साहू (मेयर पटना), आमिर सुबहानी (अध्यक्ष, बीपीएससी), विकास वैभव (आईजी), प्रत्यय अमृत (आईएएस), अंजनी सिंह (आईएएस), शीला ईरानी (आईपीएस), फिरोज आलम (डीएसपी), राकेश कुमार (डीएसपी) भी मौजूद थे। मौके पर चौधरी ने कहा कि प्रयास आईएएस एकेडमी की स्थापना बिहार के अभ्यर्थियों के सपनों को मूर्त रूप देने का ऐसा प्रयास है, जिसमें देश के अनुभवी मेंटर्स पहली बार पटना में अपनी अमूल्य सेवाएं बिहार के दुरस्थ एवं ग्रामीण अभ्यर्थियों को देंगे। प्रयास आईएएस के प्रबंध निदेशक राहुल राज ने कहा कि बिहार विश्व भर में बौद्धिक ज्ञान का केंद्र रहा है। मुकेश सहाय (एकेडमिक डायरेक्टर) ने बताया कि हर साल यूपीएससी में बिहार और पूर्वी भारत के लोग उतीर्ण होते हैं। लेकिन उन्हें तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इस संस्थान को बिहार में शुरू करने का मकसद छात्रों को यूपीएससी की तैयारी के लिए बिहार में ही सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमारे संस्थान में गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधा होगी। गरीब मेधावी छात्रों के लिए 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए तीन महीने के कोर्स का चार्ज मात्र 3,100 रुपये रखा गया है।

प्रयास आईएएस एकेडमी के उद्घाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

प्रयास आईएएस एकेडमी का उद्घाटन

पटना। प्रयास आईएएस एकेडमी का उद्घाटन बुधवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सीता साहू सहित कई उपस्थित रहे। प्रयास आईएएस के प्रबंध निदेशक राहुल राज ने कहा संस्थान में कई विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाया गया है। मुकेश सहाय (एकेडमिक निदेशक) ने बताया कि 70 वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए 3 माह के कोर्स की फीस मात्र 3100 रुपए रखा गया है।

پریاس آئی اے ایس اکیڈمی کا سمراٹ چودھری نے کیا افتتاح

खबरें एक नजर में

प्रयास आईएएस एकेडमी का शुभारंभ

पटना। प्रयास आईएएस एकेडमी का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस अवसर पर महेश्वर हजारी (उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा), हरि सहनी (विधान पार्षद), जीवन कुमार (विधान पार्षद), आशुतोष रवि (दानापुर जज), सीता साहू (मेयर पटना), आमिर सुबहानी (अध्यक्ष, बीपीएससी), विकास वैभव (आईजी), प्रत्यय अमृत (आईएएस), अंजनी सिंह (आईएएस), शीला ईरानी (आईपीएस), फिरोज आलम (डीएसपी), राकेश कुमार (डीएसपी) भी मौजूद थे। मौके पर चौधरी ने कहा कि प्रयास आईएएस एकेडमी की स्थापना बिहार के अभ्यर्थियों के सपनों को मूर्त रूप देने का ऐसा प्रयास है, जिसमें देश के अनुभवी मेंटर्स पहली बार पटना में अपनी अमूल्य सेवाएं बिहार के दुरस्थ एवं ग्रामीण अभ्यर्थियों को देंगे। प्रयास आईएएस के प्रबंध निदेशक राहुल राज ने कहा कि बिहार विश्व भर में बौद्धिक ज्ञान का केंद्र रहा है। मुकेश सहाय (एकेडमिक डायरेक्टर) ने बताया कि हर साल यूपीएससी में बिहार और पूर्वी भारत के लोग उतीर्ण होते हैं। लेकिन उन्हें तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इस संस्थान को बिहार में शुरू करने का मकसद छात्रों को यूपीएससी की तैयारी के लिए बिहार में ही सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमारे संस्थान में गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधा होगी। गरीब मेधावी छात्रों के लिए 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए तीन महीने के कोर्स का चार्ज मात्र 3,100 रुपये रखा गया है।

प्रयास आईएएस एकेडमी का उद्घाटन

पटना | प्रयास आईएएस एकेडमी का विधिवत शुभारंभ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर शामिल होने वाले अन्य गणमान्य अतिथि थे महेश्वर हजारी (उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा), हरि सहनी (सदस्य विधान परिषद), जीवन कुमार (सदस्य विधान परिषद), आशुतोष रवि (दानापुर जज) आदि। एकेडमिक डायरेक्टर मुकेश सहाय ने बताया कि हर साल यूपीएससी में बिहार और पूर्वी भारत के लोग उतीर्ण होते हैं, लेकिन उन्हे तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता हैं। अब ऐसा नहीं होगा।

प्रयास आइएएस से युवाओं के सपने होंगे पूरे : सम्राट

पटना. प्रयास आइएएस एकेडमी की स्थापना बिहार के अभ्यर्थियों के सपनों को सकार करेगी. देश के अनुभवी मेंटर्स पहली बार पटना में अपनी अमूल्य सेवाएं बिहार के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को देंगे. उक्त बातें बुधवार को प्रयास आइएएस एकेडमी का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं. इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधान पार्षद हरि सहनी व जीवन कुमार मौजूद थे. एकेडमिक डायरेक्टर मुकेश सहाय ने कहा कि प्रयास आइएएस का मकसद सिविल सेवा (यूपीएससी व बीपीएससी) की तैयारी दिल्ली के तर्ज पर पटना में प्रदान करना. प्रयास आइएएस के प्रबंध निदेशक राहुल राज ने कहा कि एकेडमिक डायरेक्टर मुकेश सहाय सर का इस क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव हैं. उनके मार्गदर्शन में अब तक पूरे भारत में सैकड़ों छात्र सिविल सेवा के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. मुकेश सहाय ने बताया कि हमारे संस्थान में गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधा होगी.

More info Call us:
8818810183 | 8818810184

prayasiasacademy prayasiasacademy prayasiasacademy.com

प्रयास
IAS ACADEMY

An Institute For **UPSC & BPSC**

Pushpanjali Palace,
Boring Road Chauraha, Patna-800001

8818810183 | 8818810184

www.prayasiasacademy.com

prayasiasacademy101@gmail.com

prayasiasacademy